मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- झाड़ू लगाने के लिये नहीं, सिस्टम दुरूस्त करने को रखे जाते हैं आइएएस! 3
- ड्रामा पशु पक्षियों की सेवा, वास्तव में बना मेनका का मेवा 4
- फारूकी विवाद के बहाने-कब बलात्कार, बलात्कार नहीं होता ? 5
- एसीपी फ़ौगाट को बधाई, आखिर कोई तो कानूनी रीढ़ वाला दिखा 8

वर्ष 29 अंक 22 फरीदाबाद, शनिवार 1-15 अक्तूबर 2016 फोन : - 9999595632 ₹ 2

फ़सल नहीं लगाई तो भी बीमा की किश्त गंवाई

फ़सल बीमा के नाम पर किसानों की लूट

खेती एक निहायत ही घाटे का सौदा बन चुकी है। इससे उबरने के लिये किसान ज्यों-ज्यों तथाकथित उन्नत बीजों व दवाओं के लिये कर्ज़ लेते जाते हैं त्यों-त्यों कर्ज़ की गहरी दलदल में धंसते जाते हैं और अन्त में आत्महत्या करके ही उससे मुक्ति पाते हैं। कर्ज़ लेकर खरीदे गये महंगे बीज व दवाओं के प्रयोग के बाद जब किसान की फ़सल किन्हीं कारणों से बर्बाद हो जाती है तो उससे बचाव के नाम पर संघी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बड़ी धूम-धाम व ढोल-धमाके के साथ फ़सल बीमा योजना शुरु की। मोदी सरकार जिसे आज अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बता रही है वही फ़सल बीमा योजना अपने आप में एक बड़ा घोटाला है, किसानों के साथ बड़ा धोखा है।

प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफ़बीवाइ) के तेज़ी से विस्तार के संकेत है और इसके तहत इस बार खरीफ़ फ़सलों के लिये घोषित राशि पिछले साल की तुलना में 70.फीसद बढ़ कर 1.18 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। खरीफ़ सत्र 2015 में फ़सल बीमा योजना के तहत 69,360 करोड़ रुपए का बीमा कराया गया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2016-17 के खरीफ़ सत्र में अब तक 3.15 करोड़ किसानों ने पीएमएफ़बीवाइ का लाभ उठाया। पिछले साल के मुबाकले इस साल यह संख्या 3.09 करोड़ है। कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव आशीष भूटानी ने बताया कि खरीफ़ 2016 में अभी तक 3.15 करोड़ किसानों ने यह योजना अपनाई है। इस बारे में बैंकों से अंतिम आंकड़े प्राप्त नहीं हुए है। बीमा की गई राशि की मात्रा 71 फ़ीसद बढ़ कर 1,18,426 करोड़ रुपये हो गई है। लेकिन मोदी सरकार के कृषि मन्त्रालय ने यह नहीं बताया कि किसानों को कितना मुआवज़ा दिया गया तथा बीमा कम्पनियों ने कितना मुनाफ़ा कूटा।

मज़दूर मार्चा, पलवल ब्यूरो

धोखे का यह कारोबार चलाने के लिये मोदी सरकार ने एक निजी (अमेरिकी) बैंक आईसीआईसीआई द्वारा संचालित लोम्बार्ड बीमा कम्पनी को चुना है। वैसे लूट एवं मुनाफ़े का यह धंधा भारत सरकार की चार कम्पनियों-नेशनल, युनाइटेड, ओरियंटल व न्यू इंडिया के द्वारा भी किया जा सकता था। परन्तु घोटाले व रिश्वत देने की जो क्षमता विदेशी कम्पनियों में होती है वह सरकारियों में नहीं हो सकती। जाहिर है इसी आधार पर सरकार ने अपनी चारों कम्पनियों की बजाय इस आइसीआईसीआई लोम्बार्ड को चुना है।

धोखाधड़ी का यह करोबार यूं तो पूरे देश में चला कर किसानों को लूटा जा रहा है, लेकिन पलवल के कांग्रेसी विधायक कर्ण दलाल ने पहली बार उदाहरण पेश करते हुए किसानों की इस लूट एवं धोखा-धड़ी के विरुद्ध थाना चांदहट में आपराधिक मुकदमा दर्ज़ कराया है। इसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ-साथ हरियाणा सरकार के कृषि विभाग एवं मन्त्रियों तक को पार्टी बनाया गया है। उपलब्ध पुख्ता जानकारी के अनुसार गांव किठवाड़ी व आसपास के 10 किसानों ने अपनी शिकायत में लिखा है कि कम्पनी ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिल कर उनके किसान क्रैडिट (बैंक) खातों से बिना उनसे पूछे पैसा निकाल लिया।

सर्वविदित है कि बीमा या कोई वित्तीय सौदा करने से पहले सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाता है। फ़सल बीमा योजना में भी आवेदन फ़ार्म का प्रावधान है। लेकिन इसके बावजूद किसानों से आवेदन लिये बगैर ही उनकी फ़सलों का बीमा कर के किश्त की रकम उनके खातों से उड़ा ली गयी। इस योजना की सबसे बड़ी धोखा-धड़ी की मिसाल बतौर इन किसानों ने बताया कि उन्होंने खेतों में कुछ बोया ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी यह ज़मीन ईस्टर्न पेरिफ़ेरियल रोड कुंडली-गाज़ियाबाद-पलवल सड़क निर्माण करने वाली कम्पनी को कुछ वर्षों के लिये पट्टे पर दे रखी है जिस पर कम्पनी ने अपना दफ़्तर एवं साजो-सामान रखने का यार्ड बना रखा है। किसी कम्पनी एवं सरकारी विभाग द्वारा धोखा-धड़ी एवं खुली लूट की इस से बेहतरीन मिसाल शायद ही कोई और मिल पाये।

उक्त किसानों की मानें तो बीमा कम्पनी ने किश्त के नाम पर एक लाख रुपये से अधिक की रकम उनके खातों से जबरन निकाल लिये। हरियाणा भर में इस तरह के मामलों की संख्या लाखों में नहीं तो हज़ारों में जरूर है। और किसानों से लूटी गयी इस हज़ारों लाख करोड़ का मतलब समझना कोई मुश्किल काम नहीं। लूट की यह मोटी रकम कोई कम्पनी अकेले-अकेले तो डकार नहीं साकती; वैसे भी बीमा के कारोबार में एजेंट के लिये कमीशन का प्रावधान तो कानूनी तौर पर रहता है। कानून में बेशक कमीशन को रिश्वत न माना जाय परन्तु जबरन किश्त वसूली पर कमीशन का दिया जाना रिश्वत व घोटाले की श्रेणी में आता है।

अब अपनी खाल बचाने के लिये राज्य के कृषि मन्त्री ओम प्रकाश धनखड़ एवं उनके भोंपू यह कहते घूम रहे हैं कि फ़सल बीमा योजना की मांग एवं चर्चा तो ताऊ देवी लाल व हुड्डा सरकार के जमाने से चली आ रही है। चली होगी लेकिन उन्होंने किया तो कुछ नहीं और कुछ न करने का कारण बड़ा स्पष्ट है कि यह योजना व्यवहारिक हो ही नहीं सकती। कोई भी बीमा कम्पनी केवल अपने मुनाफ़े के लिये चलाई जाती है। यदि उसे घाटा होने लगा तो कम्पनी तो डूब जायेगी। किसानों की फ़सल ने तो बर्बाद होना ही होता है, यदि उनका मुआवज़ा कम्पनी देने लगी तो कम्पनी एक कदम भी न चल पाये। मोदी की इस योजना में ऐसे-ऐसे किसान विरोधी प्रावधान किये गये हैं कि एक किसान को भी बीमा क्लेम न मिले। फ़िलहाल पलवल में सामने आये इस मामले को लेकर विधायक दलाल ने हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है क्योंकि पुलिस तो खुद चोरों के आधीन काम करने को मजबूर है।

इस सरकारी घोटाले के विरुद्ध हरियाणा कृषि विभाग के तमाम एडीओ (कृषि विकास अधिकारियों) में भारी रोष पनप रहा है जिसका प्रदर्शन उन्होंने खुले रूप से 29 सितम्बर को झज्जर शहर में करते हुए हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। उधर सम्बन्धित बैंक मैनेजरों ने भी इस तरह, बिना खातेदारों की मर्जी के, जबरन पैसा निकलवाने के विरुद्ध आवाज़ उठानी शुरू कर दी है।

सर्जिकल स्ट्राइक पर भारतीय सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि इसे दोहराने का इरादा नहीं है । उधर पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता का कहना था कि यदि पुनः ऐसा किया गया तो करारा जवाब दिया जायेगा। हमारे राष्ट्रवाद और उनके आतंकवाद में ऐसा सर्जिकल सामंजस्य अमेरिकी आशीर्वाद से ही संभव हो सकता है ।

ख़बर दार

कपिल बना भ्रष्टाचार का ब्रांड एम्बैसडर

कॉमेडियन कपिल शर्मा को पता नहीं था कि भ्रष्टाचार की बात करना इतना महंगा पड़ेगा कि उसे ही भ्रष्टाचार का ब्रांड एम्बैसडर बना कर छोड़ दिया जायेगा। जग जाहिर है कि बी एम सी (बॉम्बे म्यूनिसिपल कार्पोरेशन) में कदम-कदम पर रिश्वत का बाज़ार गर्म है। कपित शर्मा से 5 लाख मांगे गये तो सालाना 16 करोड़ आयकर देने वाले इस भाई को ताव आ गया। ग़लती यह हुई कपिल से कि उसने मोदी की दुखती रग को दबा दिया यह पूछ कर कि क्या यही अच्छे दिन हैं ? तब से 'न खाऊंगा न खाने दूंगा' का उद्घोष करने वाले मोदी के इशारे पर सारा शासन, प्रशासन कपिल के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। इतनी मजाल कि एक हंसने-हंसाने वाला 56 इन्च सीने वाले मोदी को ललकारे। वेसे तो कपिल की बोलती बंद है फ़िर भी 'मज़दूर मोर्चा' ने यह काल्पनिक साक्षात्कार जुटा ही लिया।

म.मो.-कपिल जी अब तो विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज ने यूएनओ में कह दिया है कि जिनके महल शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फ़ेंकने चाहिये। फ़िर आपको रिश्वतखोरी की शिकायत की क्या पड़ी थी? आपने भी तो नियमों का उल्लंघन करके अपना बंगला बनवाया है।

कपिल-भैया मैं तो मोदी की जुमलेबाज़ी का शिकार हो गया। वरना मुझे क्या पड़ी थी इस फटे में टांग अड़ाने की। जिस कॉलोनी में मैंने बंगला बनवाया है उसमें ऐसे सैंकड़ों बंगले पहले से ही बने हुए थे। वे सब बड़े नाम वालों के हैं। अब मेरा नाम भी तो बड़ा हो गया है। मैंने सोचा कि बड़े नाम वालों से रिश्वत मांगने की भला किसकी हिम्मत हो सकती है। इसलिये जब मुझसे रिश्वत मांगी गयी तो बुरा लग गया और मैंने ट्विटर पर मोदी जी को उनका जुमला याद कराने की गुस्ताखी कर दी। कहां तो कॉमेडी करता था और कहां ट्रेजडी में फ़ंस गया।

म.मो.-जब सैंकड़ों लोगों ने अनियमितता कर रखी है तो मुकदमा सिर्फ़ आपके खिलाफ़ क्यों दर्ज़ हुआ? इतने बड़े पैमाने पर अनाधिकृत निर्माण का मतलब ही हुआ कि बी एम सी भ्रष्टाचार का गटर है जिसे तुरंत साफ़ करने की जरूरत है। सरकार को बीएमसी वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये और कौन से सबूत चाहिये?

कपिल-अरे भैया यहां तो जो मुंह खोलता है उसी का ही मुंह सिला जाता है। मेरा टेंटुआ तो इस कदर दबा हुआ है कि तुम्हारे सवाल का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। वैसे अक्खा मुबई में बच्चे-बच्चे को बीएमसी की रिश्वतखोरी का पता है और मुझ से कह रहे हैं कि रिश्वत मांगने वाले का नाम बताओ। एक ट्विट करने पर तो इतनी फ़जीहत हुई, कहीं नाम ले लिया होता तो अंजाम सोच कर ही दिल कांप-कांप उठता है। अब तो हमने सिद्धांत बना लिया है कि एक चुप सौ सुख। बोलेंगे तो अपने कॉमेडी शो में अन्यथा अच्छे दिनों का राग ही अलापेंगे।

यू एन में सुषमा की जीत बेमानी

नवाज शरीफ के गर्जन के बाद यू एन में सुषमा स्वराज के ठन्डे स्वर में दिए माकूल जवाब को भारतीय मीडिया भारत की पाकिस्तान पर कूटनीतिक जीत बताते नहीं थक रहा। हर वर्ष सितम्बर के महीने में यू एन में भारत पाक के बीच यही तमाशा होता है । लगभग खाली हॉल में नहले पर दहले का शाब्दिक खेल न कहीं पहुंचता है न अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की उसमें दिलचस्पी रह गयी है।

काश्मीर मुद्दा और पाकिस्तान पर्यायवाची नहीं हैं। फिर भी काश्मीर के सन्दर्भ में पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण पहलू बन चुका है। युद्धों में पाकिस्तान को हराकर और यहाँ तक कि उसे विखंडित (बांग्लादेश) करने की हद तक अस्थिर कर भी भारत की बात बनी नहीं। कूटनीति के नाम पर सारी दुनिया में बेहद खर्चीले प्रचार अभियान चलाकर और यहाँ तक कि द्विपक्षीय गूंगी-बहरी बातचीतों एवं मुशर्रफों और नवाज शरीफों की मिन्नतें कर के भी बात नहीं बनी । एक और युद्ध या कूटनीतिक पहल से काश्मीर में कुछ बदलने नहीं जा रहा।

वैसे इन आतंकवादी वर्षों में पाकिस्तान के साथ भारतीय वैमनस्य भी कम फलदायी नहीं रहा। आज पाकिस्तान के चार में से तीन प्रांत उग्र अलगाववादी आन्दोलनों की चपेट में हैं और पूरा देश आतंकवाद की हिंसक मार झेल रहा है। इसमें भारतीय सत्ता प्रतिष्ठानों ने भी लगातार अपना सक्रिय योगदान दिया है। फिलहाल वहां यही सब चलता भी रहेगा। हालाँकि आज की परिस्थितियों में न पाकिस्तान की सैनिक मात संभव है और न कूटनीतिक। हां उसे रणनीतिक मात दी जा सकती है ।

भारत के हित में जरूरी है कि काश्मीर पर ध्यान दिया जाय न कि हर जगह पाकिस्तान-पाकिस्तान का शोर मचाकर काश्मीर से ध्यान हटाने पर। तुरंत वहां की भयंकर भूलों को दुरुस्त किया जाय। 1948 का भारत-काश्मीर समझौता पूर्णतया लागू हो, राज्य में असली प्रतिनिधि सरकार बने, नागरिकों के बीच से सैन्य-बलों को हटाया जाय, काश्मीरी पंडितों को वापस सुरक्षित बसाया जाय और केंद्र व राज्य सरकारों की मिली भगत से अर्से से चल रहा महाभ्रष्ट सहायता-सब्सिडी तंत्र दुरुस्त हो। काश्मीर पर पाकिस्तान की रणनीतिक मात के लिए उसे कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने का भी यही रास्ता है। सवाल है क्या हमारे हुक्मरानों में देश और काश्मीरियों के हक में सोचने की क्षमता है ?